ग्वालियर | गुरुवार | 16 जुलाई 2026 | वर्ष 31 | अंक 331 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित सर्वोपरि 1934 से

2 — 3 करोड़ युवाओं को रोजगार

4 — जगन्नाथ दर्शन की स्मृति मेरे मन से मिटी नहीं

9 — शुद्ध पेट्रोल खरीदने का भी मिलेगा विकल्प

10 — 28 साल बाद स्पेनिश डिफेंडर का रिकॉर्ड

एक नजर में

कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट का डेटा लीक

कुडनकुलम. तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़े डेटा लीक के दावे के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, हैकर समूह 'वर्ल्ड लीक्स' ने डार्क वेब पर प्लांट से जुड़े हजारों दस्तावेज अपलोड करने का दावा किया है। इन दस्तावेजों में कथित तौर पर कुछ हिस्सों के ब्लूप्रिंट, सप्लायरों की जानकारी, कंट्रोल रूम से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी दस्तावेज शामिल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, यह डेटा लीक एक थर्ड पार्टी डेटा सेंटर कंपनी के सर्वर से जुड़ा है। कुडनकुलम परियोजना की यूनिट-3 और यूनिट-4 से जुड़े कुछ डेटा रिलायंस समूह के माध्यम से योट्टा कंपनी के सर्वर पर मौजूद थे।

तीन राज्यों में एसआईआर की तारीख बढ़ीं

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने दिल्ली, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समयसीमा बढ़ा दी है। इस फैसले के बाद मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटाने या सुधार कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। दिल्ली में एसआईआर कार्यक्रम को 12 दिन आगे बढ़ाया गया है। अब बूथ लेवल अधिकारियों का घर-घर सत्यापन अभियान 8 अगस्त तक चलेगा, जो पहले 29 जुलाई तक प्रस्तावित था।

नई यूरिया नीति को मंजूरी

कैबिनेट फैसला : आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मजबूती

नई दिल्ली, 15 जुलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया-2026 की राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दे दी. उर्वरक विभाग द्वारा प्रस्तुत इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश में गैस-आधारित नई यूरिया निर्माण इकाइयों की स्थापना को आकर्षित करना है, ताकि घरेलू उत्पादन बढ़े और आयात पर निर्भरता कम हो.

2012 में शुरू की गई पुरानी निवेश नीति के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित हुई थीं। इस नीति की समयसीमा अक्टूबर 2019 में समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में देश में 33 यूरिया इकाइयां संचालित हैं, जिनकी कुल क्षमता 269.42 लाख मीट्रिक टन है। फिर भी घरेलू उत्पादन और मांग के बीच अंतर बना हुआ है, जिसे आयात से पूरा किया जाता है। उर्वरक विभाग को कई नए प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद नई निवेश नीति की आवश्यकता महसूस की गई।

नई नीति 2026 के तहत नई यूरिया इकाइयों की स्थापना को गति देगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह फैसला किसानों को सस्ते और पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराने तथा देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

नीति के प्रमुख फायदे

- **पारदर्शिता बढ़ेगी :** निश्चित और परिवर्तनशील लागतों को अलग-अलग किया जाएगा।
- **व्यावहारिक रिटर्न :** इक्विटी पर रिटर्न के लिए 12 प्रतिशत न्यूनतम और 16 प्रतिशत अधिकतम सीमा तय।
- **विदेशी मुद्रा जोखिम कम :** चार साल बाद निश्चित लागत को रुपये में बदलने का प्रावधान।
- **बड़ी बचत :** एनआईपी-2012 की तुलना में प्रत्येक नए संयंत्र पर 250 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होने का अनुमान.

62,500 करोड़ की नई योजना मंजूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। 62,500 करोड़ के बजट वाली यह योजना भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ाने, घरेलू स्तर पर अधिक पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने, सप्लाई चेन मजबूत करने और भारतीय मोबाइल ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी। इसके तहत भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को पात्र बिक्री पर 2.25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिया जाएगा। यदि कंपनियां मोबाइल फोन के प्रमुख पुर्जे और सब-असेंबली भारत से खरीदती हैं तो उन्हें 1.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा। वहीं, भारतीय ब्रांडों को डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पात्र बिक्री पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार के अनुसार, इस योजना के दौरान देश में मोबाइल फोन का कुल उत्पादन करीब ?39 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। साथ ही मोबाइल फोन के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। योजना से लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

1.27 लाख करोड़ से बनेगा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए 1,27,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, विनिर्माण और अनुसंधान का मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना तथा देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाना है। सरकार ने बताया कि सेमीकॉन 2.0 छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगा। पहले स्तंभ के तहत चिप डिज़ाइन को बढ़ावा दिया जाएगा।

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि सुनवाई 12 अगस्त को होगी

नई दिल्ली, 15 जुलाई. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने मामले को अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया. अदालत ने यह कदम तब उठाया, जब हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकीलों ने बताया कि याचिकाकर्ताओं के बीच आपसी बातचीत चल रही है.

भारतीय महिला टेस्ट टीम ने इतिहास रचा!

लखन पटेल को पशुपालन विभाग से हटाया

- आनंद विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार रहेंगे पटेल
- स्टेट हेंगर में सीएम ने किया मंत्री को तलब

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 15 जुलाई. प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल से विभाग वापस ले लिया गया है. उनके पास केवल आनंद विभाग रहेगा.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार सबेरे पटेल को स्टेट हेंगर तलब किया और उन्हें विभाग वापस लिए जाने की जानकारी दी. उसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन के लिए रवाना हो गए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने फिलहाल पशुपालन विभाग अपने पास ही रखा है. लखन पटेल को भले ही बुधवार सबेरे विभाग वापस लिए जाने की जानकारी दी गई हो, लेकिन उनका विभाग वापस लिए जाने का फैसला मंगलवार को ही हो गया था. राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है. ये अधिसूचना 14 जुलाई को जारी की गई है, जिसमें लखन पटेल के पास केवल आनंद विभाग रहने और पशुपालन विभाग सीएम को सौंपे जाने का उल्लेख है. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास मंगलवार रात लखन पटेल को लेकर दिल्ली से फोन आया था.

सीएम के पास अब 11 विभागों की जिम्मेदारी

सीएम के पास पशुपालन और डेयरी विभाग मिलाकर कुल 11 विभाग की जिम्मेदारी है. इनमें गृह, जेल, सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, विमानन विभाग, खनिज साधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय विभाग शामिल हैं.

अमेरिका ने 7 घंटे तक ईरान पर बम बरसाए

- ईरान पर चौथे दिन अमेरिकी हमला
- होर्मुज में बढ़ा तनाव, भारत भी सतर्क

तेहरान, 15 जुलाई. अमेरिका ने रात दक्षिणी ईरान के तटीय शहर सीरिक समेत कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, सात घंटे तक चले अभियान में होर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों तथा तटीय रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया.

यह लगातार चौथा दिन है जब अमेरिका ने ईरान में सैन्य कार्रवाई की है. दूसरी ओर, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उसने जवाबी अभियान के तहत बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं. संगठन ने बहरीन स्थित अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट बेस और जॉर्डन के अजराक एयरबेस को निशाना बनाने का दावा भी किया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तेहरान समझौते की दिशा में आगे नहीं बढ़ता है तो अगले सप्ताह बिजलीघरों और पुलों जैसे बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत से जुड़े 11 जहाज और 148 भारतीय नाविक फिलहाल फारस की खाड़ी में मौजूद हैं और होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही का इंतजार कर रहे हैं.

अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा : ईरान

वहीं ईरान ने कहा है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपनी रणनीति जारी रखेगा. तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं. ईरान के अनुसार, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी स्वरूप फायरिंग के बाद दो जहाजों को रोक दिया. हालांकि, इन जहाजों की राष्ट्रीयता और गंतव्य की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. भारत के लिए भी यह घटनाक्रम चिंता का विषय बन गया है.

सीईटीए भारत-यूके की साझेदारी में महत्वपूर्ण क्षण : मोदी

30 चैप्टर्स आधुनिक मुक्त व्यापार समझौते में शामिल

99 % भारतीय उत्पादों को जीरो ड्यूटी का मिलेगा लाभ

नई दिल्ली, 14 जुलाई. भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता बुधवार से लागू कर दिया है. भारत-यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने पर ब्रिटेन की भारत में उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने इसे दोनों देशों के संबंधों में ऐतिहासिक क्षण बताया है.

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कैमरन ने इस समझौते को व्यापार समझौतों का 'न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड' करार दिया. उन्होंने कहा कि यह अब तक का सबसे व्यापक और आधुनिक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें 30 चैप्टर्स शामिल हैं. भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (लागू हो गया है? इस समझौते के तहत, ब्रिटेन को होने वाले भारत के 99प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ शून्य हो गया है, जिससे भारतीय निर्यात को भारी बढ़ावा मिलेगा.

भारतीय उपभोक्ताओं के लिए यूके से आने वाली लग्जरी कारें और स्कॉच व्हिस्की काफी सस्ती हो जाएंगी। यूके जाने वाले लगभग 99 प्रतिशत भारतीय उत्पादों और सेवाओं को जीरो ड्यूटी का लाभ मिलेगा.

यह समझौता भारत को यूके के 90 बिलियन डॉलर से अधिक के कृषि आयात बाजार में बेहतर पहुंच दिलाएगा.

मुख्य फायदे

- टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स-ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, मरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल्स व अन्य लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स को टैरिफ मुक्ति.
- कृषि क्षेत्र में लगभग सभी प्रोडक्ट्स को जीरो-ड्यूटी एक्सेस (कुछ संवेदनशील आइटम्स को छोड़कर).
- आईटी, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, एजुकेशन और बिजनेस सर्विसेज सेक्टर के लिए नए रास्ते.
- सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत यूके में भारतीय प्रोफेशनल्स को 5 साल तक डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से छूट.
- 1,800 भारतीय शेफ, योगा इंस्ट्रक्टर और क्लासिकल म्यूजिशियन के लिए सालाना विशेष मोबिलिटी कोटा.

आर्थिक संबंध होंगे मजबूत

भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता, दोनों देशों की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है. इससे हमारे आर्थिक संबंध और गहरे होंगे. यह बयान बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के भारत-यूके सीईटीए के लागू होने की पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कोट करते हुए लिखा, यह भारत-यूनाइटेड किंगडम साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है.

11 ठिकानों पर एसीबी के छापे में मिली 100 करोड़ की संपत्ति

हैदराबाद, 15 जुलाई. तेलंगाना में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर बी. रविंदर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। एसीबी की छापेमारी में कई संपत्तियों के दस्तावेज, नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान बरामद होने का दावा किया गया है.

एचएमडीए चीफ इंजीनियर पर कसा शिकंजा

1,440 ग्राम सोने के आभूषण 12.5 किलो चांदी मिली

3.82 लाख रुपये नकद और 45.05 लाख रुपये के बैंक डिपॉजिट मिला

एसीबी के अनुसार, दस्तावेजों में जब्त संपत्तियों की कीमत करीब 9.24 करोड़ रुपये है, जबकि इनकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये आंकी गई है. एजेंसी ने बताया कि मंगलवार को बी. रविंदर के घर, कार्यालय और उनसे जुड़े नौ अन्य ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। जांच के दौरान हैदराबाद के विभिन्न इलाकों में पांच खाली प्लॉट, चार रिहायशी फ्लैट, करीब चार एकड़ कृषि भूमि, एक अर्धनिर्मित विला और एक कमर्शियल-कम-रेजिडेंशियल भवन के दस्तावेज मिलने की बात सामने आई है। एसीबी ने बताया कि तलाशी में करीब 3.82 लाख रुपये नकद, 45.05 लाख रुपये के बैंक डिपॉजिट, 1,440 ग्राम सोने के आभूषण, 12.5 किलो चांदी और लाखों रुपये के घरेलू सामान भी बरामद किए हैं।

एसीबी अधिकारियों के अनुसार, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कीमत और बाजार कीमत में बड़ा अंतर होने के कारण दस्तावेजी मूल्य कम और वास्तविक बाजार मूल्य ज्यादा हो सकता है। जांच पूरी होने के बाद ही संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल आरोपी अधिकारी को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसीबी का कहना है कि जांच के दौरान और भी संपत्तियों का खुलासा हो सकता है।